नफरत फैलाने वालों पर फेसबुक का चाबुक

सैन फ्रांसिस्को, एपी: सोशल मीडिया पर नफरत और कट्टरता पर नकेल कसने के पड़ रहे दबावों के बीच फेसबुक ने एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने चरमपंथी संगठन 'नेशन ऑफ इस्लाम' के कर्ताधर्ता लुइस फर्रखान और विवादास्पद राजनीतिक शख्सियत एलेक्स जोन्स पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि इन लोगों ने उसकी नीतियों का उल्लंघन किया है।

कंपनी ने जोन्स की वेबसाइट सहित गोरों को श्रेष्ठ बताने वाले पॉल नेहलेन, राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार रहे रोजर स्टोन, चरमपंथी मिलो यायनोपोलोस, पॉल जोसेफ वाटसन और लॉरा लूमर को भी प्रतिबंधित कर दिया है। ट्विटर ने भी लूमर, जोन्स और यायनोपोलोस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनके ऊपर लगाए गए प्रतिबंध फेसबुक की प्रमुख सर्विस और इंस्टाग्राम दोनों पर लागू

'नेशन ऑफ इस्लाम' के कर्ताधर्ता लुइस फर्रखान सहित अन्य बड़े चरमपंथियों के खातों को किया बैन

होंगे। इतना ही नहीं अगर कोई व्यक्ति इनकी प्रशंसा करते हुए कोई पोस्ट करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।

अभी भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं चरमपंथी : अमेरिका में भड़काऊ समूहों को ट्रैक करने वाले एक संस्थान के वरिष्ठ शोध विश्लेषक केगन हैंक्स ने कहा कि हम जानते हैं कि अभी भी दोनों सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सक्रिय हैं और इसका प्रयोग नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं। फेसबुक के पूर्व कार्यकारी और हार्वर्ड में इंटरनेट नीति के विशेषज्ञ दीपायन घोष ने कहा कि प्रतिबंध उतना बड़ा कदम नहीं है जितना कि कंपनी इसे बता रही है। जोन्स जैसे बड़े फॉलोवर वाले लोगों को प्रतिबंधित करना कंपनी के व्यवसायिक हित के खिलाफ है।

प्रतिबंध पर भड़के चरमपंथी : प्रतिबंध पर टिप्पणी करते हुए मिलो यायनोपोलोस ने केवल एक ई-मेल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगला नंबर आपका है। वहीं जोन्स ने अपनी वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान गुस्से में कहा कि कंपनी ने सिर्फ मुझ पर प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि उसने मुझे बदनाम किया है। आखिर जुकरबर्ग ने ऐसा क्यों किया। वहीं वाटसन ने ट्वीट करके कहा कि मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है।

90,000 यूट्यूब वीडियो ने आतंकी नीति का उल्लंघन किया: गूगल ने कहा कि उसने 2019 की पहली तिमाही में यूट्यूब के एक मिलियन से अधिक संदिग्ध आतंकी वीडियो की समीक्षा की और पाया कि 90,000 के लगभग वीडियो कंपनी की आतंकवाद नीति का उल्लंघन करते हैं। गृह सुरक्षा पर अमेरिकी समिति को भेजे गए पत्र में गूगल ने यह बात कही है। वहीं अमेरिकी समिति को भेजे एक अन्य पत्र में ट्विटर ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के प्रयासों के चलते उसने एक अगस्त 2015 से 30 जून, 2018 के बीच 14 लाख से अधिक खातों को निलंबित कर दिया है।

न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने की सगाई, जल्द रचाएंगी शादी

वेलिंगटन, एएफपी : न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा एरडर्न जल्द ही अपने पार्टनर क्लार्क गेफोर्ड से शादी करेंगी। जेसिंडा और क्लार्क लंबे समय से साथ रह रहे हैं और पिछले साल दोनों को एक बेटी हुई थी। एरडर्न के प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि दोनों ने ईस्टर की छुट्टियों के दौरान सगाई कर ली है और वे जल्द शादी करने वाले हैं। शादी की तारीख अभी नहीं बताई गई है।

38 वर्षीय एरडर्न ने पिछले साल अपनी बेटी नेव को जन्म दिया था। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बाद वह विश्व की दूसरी महिला हैं जिन्होंने पीएम पद पर रहते हुए बच्चे को जन्म दिया। खुद को नारीवादी कहने वाली एरडर्न अपनी बेटी को लेकर संयुक्त राष्ट्र की आमसभा में भी शामिल हुई थीं। यदि वह प्रधानमंत्री रहते हुए ही शादी रचाती हैं तो वह ऐसा करने वाली दूसरी राष्ट्र प्रमुख होंगी। इससे पहले

न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा एरडर्न और क्लार्क गेफोर्ड (फाइल फोटो)।

2008 में फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने पद पर रहने के दौरान शादी की थी। एरडर्न के साथी क्लार्क टीवी होस्ट हैं लेकिन नेव के पैदा होने के बाद से वह घर पर रहकर उसकी देखरेख करते हैं। दोनों की सगाई की बात ऐसे समय पर सामने आई है जब क्राइस्टचर्च की दो मस्जिदों पर हमले के बाद से एरडर्न मुश्किल हालात का सामना कर रही थीं। इस हमले में 51 लोगों की मौत हो गई थी।

वतन लौटने से बचने को दुबई में पाक कामगार ने कर दी भारतीय की हत्या

दुबई, प्रेट्र : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में एक पाकिस्तानी कामगार ने महज इसलिए अपने भारतीय साथी की गला घोंटकर हत्या कर दी क्योंकि वह किसी भी हालत में अपने वतन वापस नहीं जाना चाहता था। 27 वर्षीय आरोपित ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल लिया है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपित का भाई उसे वापस पाकिस्तान बुलाने की धमकी दे रहा था। इसी वजह से वह कोई अपराध कर जेल जाना चाहता था ताकि उसे अपने घर वापस ना जाना पड़े। इसी मंशा से उसने 26 फरवरी को नाद ए हमार स्थित निर्माण स्थल पर सो रहे पीड़ित पर हमला कर उसका गला घोंट दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल से गिरफ्तारी पाकिस्तानी आरोपित ने तुरंत अपना जुर्म कबूल लिया था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि किसी व्यक्ति ने उसकी नंगी तस्वीर उतार कर पाकिस्तान में रह रहे उसके भाई को भेज दी थी।

कैसे बदले सुर ▶ पुलवामा हमले के बाद अमेरिका और फ्रांस के रुख से भी चीन पर बना दबाव

चीन की रजामंदी के पीछे बीआरआइ भी वजह

कई देशों में बीआरआइ को लेकर उभरे विरोध के चलते बढ़ गई है चीन की चिंता

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

दुनियाभर के रणनीतिकार अभी भी इस उधेड़बुन में हैं कि आखिरकार मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए चीन कैसे तैयार हो गया। किन वजहों ने चीन को उसकी एक दशक पुरानी नीति को बदलने के लिए मजबूर किया? दुनिया के तमाम कूटनीतिक माध्यमों से जो सूचनाएं अब सामने आ रही हैं उससे साफ है कि किसी एक वजह के बजाय कई वजहों ने चीन के मिजाज को बदलने के लिए बाध्य किया है। इनमें पुलवामा हमले के बाद अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों का खुलकर सामने आना, भारत की तरफ से चीन को एक तरह से चेतावनी देना और महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआइ) की राह में भारत का विरोध शामिल हैं।

कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक, पिछले एक वर्ष में कई देशों के भीतर बीआरआइ को लेकर विरोध शुरू हुआ है उससे चीन की चिंता बढ़ी है। इसका सबसे मुखर विरोधी भारत है। भारत ही एकमात्र देश था जिसने चीन की तरफ से बुलाई गई वर्ष 2017 की बैठक का बहिष्कार किया था। 2019 की बैठक में भारत के अलावा अमेरिका ने भी हिस्सा नहीं लिया। भारत ने ही सबसे पहले कहा था कि इस परियोजना के तहत उसकी संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है। अमेरिका, फ्रांस, जापान समेत कई देश अब भारत के इस मत का समर्थन कर रहे हैं। इसकी लागत और वित्तीय बोझ की वजह से श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों के अलावा पाकिस्तान में

भी इसके खिलाफ आवाज उठी है। बीआरआइ (पुराना नाम वन बेल्ट वन रोड) के तहत चीन सड़क, समुद्री व रेल मार्गों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तैयार करना चाहता है। इसका एक हिस्सा, जिसका नाम चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) है, गुलाम कश्मीर से गुजरता है। इस पर भारत को आपत्ति है। ऐसे में चीन ने मसूद अजहर पर अपनी नीति इस उम्मीद से बदली है कि भारत का विरोध भी कम होगा। भारत ने जिस तरह हाल में खत्म हुई बीआरआइ बैठक को लेकर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की उसे देखते हुए भी कयास लगाया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच भीतर ही भीतर कोई रजामंदी हुई है। हालांकि भारत के आधिकारिक सूत्र इस बात से पूरी तरह से इन्कार करते हैं।

सूत्रों के मुताबिक, पुलवामा हमले के बाद जिस तरह अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन पाक स्थित आतंकी संगठन जैश के खिलाफ भारत के साथ खड़े हुए उसका भी असर चीन पर पड़ा। पुलवामा हमले में जैश की भूमिका के नए सुबूत संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति के सभी सदस्य देशों को दिए गए। नई दिल्ली में यह काम विदेश मंत्रालय ने किया तो अमेरिका और फ्रांस ने खास तौर पर अपने स्तर पर चीन के साथ सुबूतों को साझा किया। सूत्रों के मुताबिक, 'इन सुबूतों ने चीन को वीटो पावर हटाने में मदद की।' इस तरह से अजहर पर चीन के रवैये को बदलने में पुलवामा हमले की भूमिका निर्णायक रही।

अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया जाना भारत की सांकेतिक जीत : विशेषज्ञ

नई दिल्ली, आइएएनएस : विशेषज्ञों का मानना है कि जैश-ए-मुहम्मद सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया जाना भारत के लिए अहम सांकेतिक जीत है। उनका मानना है कि पुलवामा और मुंबई आतंकी हमलों के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए भारत को अपने रुख पर अडिग रहना चाहिए। पूर्व विदेश सचिव शशांक का मानना है कि चीन ने भले ही इस मामले में पाकिस्तान के साथ कुछ सलाह-मशिवरा किया हो, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षेत्र और दुनिया की स्थिति में इस कदर बदलाव आया है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करने के लिए जबर्दस्त दबाव में है। मसूद अजहर को बचाने में चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अकेला पड़ गया था। रक्षा विशेषज्ञ सी. उदय भाष्कर का मानना है कि चीन के रुख में बदलाव संभवतः श्रीलंका धमाकों के बाद विदेश सचिव विजय के. गोखले की बीजिंग यात्रा के बाद आया। दोनों ओर से कुछ लेन-देन की बात हुई होगी। हालांकि उनका यह भी मानना है कि अजहर के वैश्विक आतंकी घोषित होने से पाकिस्तान पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। नेपाल और अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रह चुके राकेश सूद का भी कहना है कि काली सूची में डालने से लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद की गतिविधियों पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा था।

सीआइए के पूर्व निदेशक ने पाक का आतंकी चेहरा किया बेनकाब

- कहा, भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर करता है आतंकवाद का इस्तेमाल
- दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में शुमार पाकिस्तान ने बना रखे हैं आतंकी संगठन

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए के कार्यकारी निदेशक रहे माइकल मोरेल ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानने वाले पाकिस्तान ने कई आतंकी संगठनों को खड़ा कर रखा है। वह इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ लड़ाई में हथियार के तौर पर करता है।

मोरेल ने कर्ट कैंपबेल और रिचर्ड वर्मा के साथ गुरुवार को एक चर्चा में कहा कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में है। कैंपबेल पूर्वी एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री रह चुके हैं, जबकि वर्मा भारत में अमेरिकी राजदूत के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मोरेल ने कहा, 'उन्हें इस बात का अहसास नहीं है कि आतंकी संगठनों को काबू में रखना असंभव है और वे अंततः आप पर ही वार करेंगे। पाकिस्तानी हुक्मरान भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करते हैं। अफगानिस्तान में भी ऐसा ही किया जाता है, क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव का डर है। इसलिए उन्होंने भारत के खिलाफ लड़ने के लिए आतंकी संगठनों को खड़ा किया है।'

पाकिस्तान पर ध्यान नहीं देता भारत : मोरेल ने कहा, 'वे अब भी भारत को पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए खतरे के तौर पर देखते हैं, जबकि भारत ने पाकिस्तान पर ध्यान देना बहुत पहले ही छोड़ दिया है। वह अपने आर्थिक भविष्य पर ध्यान दे रहा है।'

पाकिस्तान में हो सकती है क्रांति : मोरेल ने कहा कि इस दक्षिण एशियाई देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था कमजोर है। वह नौकरियां मुहैया नहीं करा सकता जिसकी युवाओं को जरूरत है। वे मजदूरी करने के लिए विवश हैं। शिक्षा प्रणाली भी ध्वस्त है। मेरा मानना है कि सामाजिक दृष्टिकोण से आतंकवाद बढ़ रहा है। यह सेना के अंदर भी बढ़ रहा है। इसलिए संभव है कि अगले पांच-दस सालों में अरब जैसी क्रांति पाकिस्तान की सड़कों पर भी देखने को मिल सकती है। इस क्रांति का अंत कट्टरपंथी सरकार के साथ हो सकता है, जिसके पास परमाणु हथियार भी होंगे। यह कितनी भयावह स्थिति होगी।

कौन हैं मोरेल

वर्ष 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में छुपकर रह रहे अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराने के अभियान में मोरेल ने भी अहम भूमिका निभाई थी। वह 2012-13 में सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी (सीआइए) के कार्यकारी निदेशक रहे। एजेंसी का डिप्टी निदेशक रहते वह कई बार पाकिस्तान गए थे।

नेपाल सेना और विशेषज्ञ ने खारिज किया येती का दावा

काठमांडू, प्रेट्र : नेपाल की सेना ने भारतीय सेना के उस दावे को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि हिमालय पर येती (हिममानव) के पदचिह्न देखे गए हैं। इससे हिमालय पर येती के होने का पता चलता है।

भारतीय सेना ने सोमवार को कहा था कि उसके पर्वतारोहण अभियान दल को नेपाल में हिमालय पर चढ़ते समय बड़े-बड़े पदचिह्न दिखाई दिए। अभियान दल के सदस्यों ने उन पदचिह्नों के फोटो भी लिए और उन्हें सार्वजनिक किया गया। पूर्व में भी हिमालय और दुनिया के अन्य बर्फीले पर्वतीय स्थानों पर हिममानव के अस्तित्व को लेकर कयास लगाए जाते रहे हैं। साइबेरिया, मध्य और पूर्वी एशिया में हिममानव को देखे जाने के दावे अतीत में किए गए हैं। नेपाल की लोकगाथाओं में भी हिममानव की चर्चा है, जो सामान्य आदमी से ज्यादा ऊंचे और बलिष्ठ होते हैं।

नौ अप्रैल, 2019 को हिमालय की यात्रा पर गए भारतीय सेना के पर्वतारोहण दल को मकालू आधार शिविर के पास 32 गुणा 15 इंच लंबे-चौड़े विशाल पदचिन्ह दिखाई दिए। मकालू के पास पहले भी हिममानव देखे जाने के दावे हुए थे। इसी के बाद सोमवार को भारतीय सेना ने ट्वीट कर हिममानव के अस्तित्व का कयास लगाया, साथ ही पदचिह्नों के फोटो जारी किए।

नेपाली सेना और नेपाल के वन्य जीव

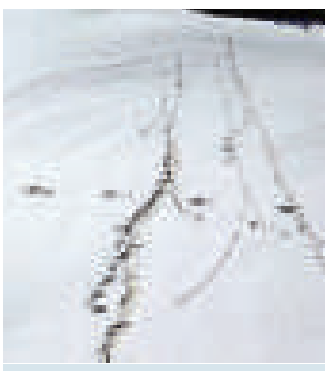

भारतीय सेना के पर्वतारोहियों को मिले थे हिम मानव बड़े-बड़े पदचिह्न

और राष्ट्रीय उद्यान विभाग के महानिदेशक मान बहादुर खड़का ने भारतीय अभियान दल के दावे को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि बर्फ पर मिले पदचिह्न हिमालयी भालू के हैं। नेपाली सेना के प्रवक्ता बिज्ञान देव पांडे ने कहा है कि तीन-चार साल पहले फ्रेंच अभियान दल के सदस्यों को भी बर्फ पर ऐसे ही निशान मिले थे। तब हुई जांच में भी भालू के पैरों के निशान होने का पता चला था। मकालू आधार शिविर के आसपास बड़ी संख्या में पोलर बियर रहते हैं। नेपाल, तिब्बत और चीन सीमा पर स्थित मकालू दुनिया का पांचवां सबसे ऊंचा पहाड़ है।

किम के सौतेले भाई की हत्यारोपी महिला रिहा

कुआलालंपुर, रायटर : उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई की हत्या की साजिश में गिरफ्तार की गई वियतनामी महिला को मलेशिया की जेल से रिहा कर दिया गया है। मलेशिया के अभियोजकों ने पिछले माह 30 साल की दोन थाई हुओंग के खिलाफ हत्या का आरोप वापस ले लिया था। इसी मामले में गिरफ्तार की गई इंडोनेशियाई महिला को इस साल फरवरी में रिहा कर दिया गया था।

कहा जाता है कि तानाशाह किम के एजेंटों ने इन दोनों महिलाओं को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर किम के सौतेले भाई जोंग नाम को फरवरी, 2017 में कुआलालंपुर हवाईअड्डे पर जहर देकर मरवा दिया था। जोंग नाम द्वारा अपनी आलोचना किए जाने से गुस्साए किम ने अपने एजेटों को सौतेले भाई की हत्या का हुक्म दिया था। इस मामले में पकड़ी गई दोनों महिलाओं को पहले मौत की सजा सुनाई गई थी। जोंग नाम की हत्या के असली साजिशकर्ता चारों उत्तर कोरियाई एजेंट फरार होने में कामयाब रहे थे।

पाक सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की शरीफ की स्थायी जमानत अर्जी

इस्लामाबाद, आइएएनएस : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को उन्हें चिकित्सकीय आधार पर स्थायी जमानत देने से इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा कि शरीफ की जान को तत्काल कोई खतरा नहीं है।

शरीफ के वकील ने इसके बाद उनकी जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की। लेकिन पीठ ने उसे भी खारिज कर दिया। भ्रष्टाचार के मामले में सात साल की सजा काट रहे शरीफ को इलाज के लिए छह हफ्तों की जमानत मिली थी, जो सात मई को खत्म हो रही है। मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा ने कहा, 'छह हफ्तों की जमानत में केवल उनके टेस्ट कराए गए। नई मेडिकल रिपोर्ट से साफ है कि उनकी जान पर कोई खतरा नहीं है इसलिए उनकी जमानत अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। सेहत खराब होने पर जेल अधीक्षक के पास उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का अधिकार होगा।'

बातचीत के बीच तालिबान ने दी अमेरिका को नसीहत

- अमेरिकी दूत के ट्वीट पर आतंकी संगठन ने दी तीखी प्रतिक्रिया

काबुल, रायटर : अफगानिस्तान में जारी संघर्ष खत्म कराने के प्रयास में जुटे अमेरिका के विशेष दूत जालमे खलीलजाद का एक ट्वीट तालिबान को नागवार गुजरा है। आतंकी संगठन ने कहा है कि खलीलजाद तालिबान से हथियार डालने की मांग करना बंद कर दें और इसकी जगह उन्हें अपने देश को बल प्रयोग बंद करने के लिए समझाना चाहिए।

अफगानिस्तान में जन्मे अमेरिकी राजनयिक खलीलजाद इस समय तालिबान के साथ कतर की राजधानी दोहा में छठे दौर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच यह बातचीत बुधवार से चल रही है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, 'हमारी वार्ता के प्रारंभिक सत्र में मैंने तालिबान से जोर देकर कहा कि अफगान लोग यानी आपके भाई-बहन इस संघर्ष को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए यह हथियार डालने, हिंसा रोकने और शांति की राह पर चलने का वक्त है।' इसके जवाब में तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कई तीखे ट्वीट किए। एक ट्वीट में मुजाहिद ने लिखा, 'उन्हें हथियार डालने के विचार को भूल जाना चाहिए। इस तरह की कल्पनाओं की जगह उन्हें अमेरिका को बल प्रयोग बंद करने के लिए समझाना चाहिए।'

तालिबान का बढ़ा प्रभाव

2001 में अफगानिस्तान की सत्ता से बेदखल होने के बाद हाल के दौर में तालिबान के हमले बढ़ गए हैं। अफगानिस्तान में उसके कब्जे या प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी है।

अफगानिस्तान में 14 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात

युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान में इस समय करीब 14 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। वे अफगान बलों को तालिबान से मुकाबले के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं।

क्वींसलैंड सरकार ने अडानी की योजना को मंजूरी नहीं दी

मेलबर्न, प्रेट्र : आस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत की सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र की भारतीय कंपनी अडानी की प्रबंधन योजना नामंजूर कर दी। अडानी ने विलुप्त हो रही ब्लैक-थ्रोटेड पक्षी की प्रजाति के संरक्षण की योजना सौंपी थी। सरकार ने कहा है कि कंपनी का प्रस्ताव अरबों डॉलर की प्रस्तावित खनन परियोजना को मंजूरी देने की शर्तों को पूरा नहीं करता है। इस फैसले से क्रैमिचाएल कोयला खान परियोजना अनिश्चितकाल तक टल सकती है।

भारतीय ऊर्जा कंपनी की राह में ब्लैक-थ्रोटेड पक्षी और भूजल योजना सबसे बड़ा रोड़ा हैं। इन दोनों के कारण भारतीय कंपनी की खनन परियोजना रुकी हुई है। भूजल योजना अभी भी प्रांतीय सरकार के पास विचाराधीन है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार क्वींसलैंड पर्यावरण अधिकारियों ने अडानी के अधिकारियों से मुलाकात की और कहा कि पक्षी प्रबंधन योजना के मौजूदा प्रारूप को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। यह अडानी के पर्यावरणीय प्राधिकार को पूरा करने में विफल है।

पर्यावरण बचाने के लिए प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में शुक्रवार को हजारों की संख्या में छात्र-छात्राओं ने सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के मुख्यालय के बाहर जलवायु परिवर्तन के प्रति आगाह करते हुए प्रदर्शन किया। इन छात्रों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसलिए आम चुनाव से पहले इस विषय पर ध्यान खींचने के लिए राजनेताओं के दफ्तरों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एएफपी

सख्ती की वजह

चीन अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। शिनजियांग में उसकी सख्ती का कारण बीआरआइ ही है...

बीआरआइ के लिए कुछ भी कर सकता है चीन

- परियोजना की सफलता के लिए सख्ती को अहम मानता है चीन
- इस अशांत चीनी प्रांत में उइगर मुस्लिमों की रहती है बड़ी आबादी

खोर्गोस (कजाखस्तान), एएफपी : चीन और कजाखस्तान की सीमा पर स्थित खोर्गोस शहर के विशेष आर्थिक जोन में कारोबारियों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है, लेकिन चीन की है स्पष्ट चेतावनी है कि किसी तरह का नकाब या लंबी दाढ़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन ने सुरक्षा संबंधी अपनी इस तरह की सख्त नीतियों को खोर्गोस समेत शिनजियांग प्रांत के पूरे सीमाई इलाकों में कड़ाई से लागू कर रखा है। चीन के इस अशांत प्रांत में उइगर मुस्लिमों की बड़ी आबादी रहती है। चीन का मानना है कि यह प्रांत राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआइ) की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

चीन ने हाल के सालों में दंगों, बम धमाकों और चाकूबाजी की घटनाओं के चलते शिनजियांग में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। उसने इस प्रांत में कई तरह की बंदिशें लगा रखी है। चीन ने व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर बनाए गए केंद्रों में लाखों मुस्लिमों को बंदी भी बना रखा है। इस पश्चिमी प्रांत के विशेषज्ञ जर्मन शोधकर्ता एड्रियन जेंस ने कहा, 'चीन की केंद्रीय सरकार का अशांत शिनजियांग को पूरी तरह अपने नियंत्रण में करने के प्रयास के पीछे का अहम कारक बीआरआइ है।'

फोरम में नहीं उठा शिनजियांग का मुद्दा : चीन ने बीआरआइ को दुनिया के सामने प्रचारित करने के लिए बीते सप्ताह बेल्ट एंड रोड फोरम को आयोजन किया था, लेकिन फोरम में हिस्सा लेने आए पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों के नेताओं ने शिनजियांग में चीन के दमन पर बोलने से कतरा गए। इन देशों के अंदर हालांकि चीन के कदम को लेकर असंतोष है, लेकिन बीआरआइ परियोजनाओं में भागीदार होने के चलते वे कुछ नहीं बोले।

इमरान को नहीं कुछ पता : गत मार्च में उइगरों के साथ चीन के अत्याचार के बारे में पूछे जाने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, 'मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।' बीआरआइ के तहत पाकिस्तान में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे समेत कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

कजाखस्तान की 16 परियोजनाओं में चीन का निवेश : कजाखस्तान कह चुका है कि चीन में रहने वाले कजाख लोगों की भलाई इस देश के साथ संबंधों के लिहाज से अहम है। कजाखस्तान ने आतंकवाद, कट्टरपंथ और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में चीन का समर्थन भी किया है। इस देश में चीन ने हाईवे और रेल समेत 16 परियोजनाओं में 41 करोड़ डॉलर का निवेश कर रखा है।

उन्नत तकनीक पाने के लिए हर हथकंडा अपनाता है चीन

- पेंटागन की रिपोर्ट ने किया रहस्योद्घाटन, कहा, हर नागरिक चीनी सत्ता के उद्देश्यों को पूरा करने में लगा

वाशिंगटन, आइएएनएस : चीन सेना के आधुनिकीकरण और उसे प्रमुख ताकत बनाने के लिए व्यापक पैमाने पर जासूसी का सहारा लेता है। इस सिलसिले में वह अन्य देशों की सेनाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को चोरी कराता है और उन्हें पाने के लिए अन्य हथकंडे अपनाता है। चीन द्वारा विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड वेहिकिल इसी तरह की तकनीक चोरी का नतीजा हैं। यह जानकारी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट में सामने आई है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपनी ताकत और प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई तरह के हथकंडों को औजार के रूप में इस्तेमाल करता है। वह विदेश में बड़ा पूंजी निवेश करता है। साइबर इन्फॉर्मेशन की चोरी करता है। निजी क्षेत्रों में काम करने वाले अपने नागरिकों का शोषण करता है। अपने इन नागरिकों के जरिये चीनी सेना संवेदनशील तकनीक तक पहुंचने की कोशिश करती है। विदेशी कंपनियों में काम करने वाले चीनी कर्मियों को वह तकनीक चीनी सेना तक पहुंचाने के लिए मजबूर किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार चीन तकनीक चोरी का कार्य आयातित वस्तुओं से, चीन में विदेशी निवेश से चल रही कंपनियों से जानकारी चोरी कराकर, विदेशी शोध, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की जानकारियां चोरी कराकर करता है। विदेशी कंपनियों के साथ चल रहे चीनी कंपनियों के संयुक्त उपक्रम, शोध और अकादमिक सहयोग कार्यक्रमों, विदेशी या विदेशी कंपनियों में काम कर चुके चीनी प्रतिभाशाली कर्मचारियों की भर्ती कर भी चीन सरकार नई तकनीक प्राप्त करने का कार्य करती है। चीन शांतिपूर्ण कार्य का उद्देश्य बताकर वह ऐसी तकनीक प्राप्त करता है लेकिन बाद में उसका उपयोग सैन्य कार्यों के लिए कर लेता है। देश में मौजूद और विदेश में कार्यरत चीन के नागरिक कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता के उद्देश्यों को पूरा करने में हर समय सजग रहते हैं।

मानव तस्करी के आरोप में दो चीनी पाकिस्तान में गिरफ्तार

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान के अधिकारियों ने मानव तस्करी के आरोप में दो चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। वे पाकिस्तानी लड़कियों से शादी कर उन्हें चीन ले जाना चाहते थे। हाल में संघीय जांच एजेंसी (एफआइए) को सूचना मिली थी कुछ चीनी नागरिक मानव अंग व्यापार और वेश्यावृत्ति के लिए पहले पाक लड़कियों से शादी करते हैं फिर उन्हें अपने देश ले जाते हैं। इसके बाद से ही एफआइए मानव तस्करी में शामिल चीनियों की तलाश कर रही थी।

उप निदेशक जमील अहमद मायो के नेतृत्व में एफआइए की टीम ने पंजाब प्रांत के फैसलाबाद स्थित एक होटल में छापा मारा। वहां ये दोनों चीनी पाक लड़कियों से शादी रचाते पकड़े गए। लड़कियों और उनके परिजनों को बयान दर्ज करने के बाद छोड़ दिया गया। पंजाब प्रांत में एफआइए के निदेशक तारिक रुस्तम ने कहा, 'पूछताछ के दौरान दोनों ने जुर्म कबूल लिया है। अभी यह पता नहीं चल सका है कितनी लड़कियों की अब तक तस्करी की जा चुकी है।'